

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : 18 फरवरी, 2006

विषय: दृष्टि विकलांगों को सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु जनपदों को प्रदेश में संचालित तीनों जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के मध्य विभाजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि प्रदेश के जनपदों, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों (District Disability Rehabilitation Centres) तथा दृष्टि विकलांगों को सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (N.I.V.H.), देहरादून (नोडल एजेंसी) के मध्य परस्पर समन्वय एवं संवाद की कमी है जिस कारण वांछित उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है।

अतः प्रदेश में स्थापित/क्रियाशील तीनों जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की अधिकारिता को प्रदेश के 13 जनपदों के मध्य निम्नानुसार विभाजित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, अल्मोड़ा - जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चमोली।
2. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, टिहरी - जनपद टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी।
3. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, हरिद्वार - जनपद हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दृष्टि विकलांगों को सहायक उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराने हेतु उक्तानुसार अपने जनपद से संबंधित जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों तथा नोडल एजेंसी से सम्पर्क/समन्वय करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव।

संख्या : 58(1)/XVII(1)-2/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. विकलांगजन आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
5. समन्वयक/प्रभारी, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, अल्मोड़ा/टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार द्वारा संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (N.I.V.H.), देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दत्तल)
उपसचिव।

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 27 जनवरी, 2006

विषय: विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-30 में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजनान्तर्गत रु. 3.20 लाख (रु. तीन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका / बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।
4. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुरार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 के 'आयोजनागत पक्ष' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-02-अनुरूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-06-विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना" के मानक मद "20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 1018/XXVII(3)/2006 दिनांक 13 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव।

क्रमशः...

